



"राइट टू रिकॉल पार्टी"



दिल्ली की पांचवीं सबसे बड़ी और असली विपक्षी पार्टी है

हमारा मानना है कि अच्छे कानूनों से हीं भारत में हम गरीबी, महंगाई, बेरोज़गारी को खत्म कर सकते हैं। हमारी पार्टी ने America जैसे देशों के वो कानून पता लगाए हैं जिस वजह से वहा इतनी तरक्की और खुशहाली हैं। ये बातें आपके नेता आपसे छुपाना चाहते हैं। निचे दिए गए 6 कानूनों की तरह ऐसे 30+ कानून हम भारत में लाकर भारत में असली व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं।

वोट वापसी



जैसा कि अमेरिका में है, हम जिला पुलिस अधीक्षक, न्यायाधीश, जिला शिक्षा अधिकारी, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री आदि पर Right to Recall (वोटवापसी) को लागू करेंगे। नागरिक इन अफसरों और नेताओं को किसी भी समय बदल सकेंगे, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। प्रशासन की कार्यक्रमशालता बेहतर होगी।

खनिज मुनाफा बटवारा



खनन से उत्पन्न होने वाली धनराशि को सभी के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा - 65% नागरिकों में बराबर और 35% सेना को। इससे गरीबी कम होगी। बेरोज़गारी के समय में युवाओं को मदद मिलेगी। वृद्धों को रिटायरमेंट के बाद सुविधा होगी। सैन्य बजट बढ़ेगा जिससे भारत की सेना मज़बूत होगी।

जनमत संघर्ष (टी.सी.पी.)



इस कानून के अंतर्गत आप अपनी मांग एक शपतपत्र में लिखकर सरकारी वेबसाइट पर दर्ज करा पाएंगे और भारत का कोई भी नागरिक उसपे हाँ/ना दर्ज कर सकेगा। इससे सरकार को नागरिकों की जायज़ मांगों को मानाने पर मजबूर होना पड़ेगा। अधिकारी जनता की शिकायत कभी दबा नहीं पाएंगे।

हमें जल्द से जल्द भारत के 100 करोड़ वोटरों को इन महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी देनी है। तभी हम भारत में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोज़गारी, चीन से युद्ध का खतरा आदि परेशानियों को जल्द सुलझा पाएंगे। **हमारा समर्थन करें।**



हमारे आन्दोलन से जुड़ें



संपर्क करें हमारे आंदोलन से जुड़ें
 (₹) राहुल तिवारी- 88106 40928
 (₹) किशन सिंह नेगी- 78140 09968

क्वांटसप्प ग्रुप
में जुड़ने के लिए स्कैन करें

<https://tinyurl.com/VoteVapsiMovement>

rrpindia.in

जूरी कोर्ट



जूरी कोर्ट में अमेरिका की तरह जज की जगह चयनित आम नागरिकों की एक जूरी हर मामले पर निर्णय देगी। फिर कोई मामला 10-20 साल तक नहीं टलेगा। इससे समाज में हर तरह का अन्याय कम होगा। फैसले निष्पक्ष होंगे। लोगों का अदालतों में जाने का डर खत्म होगा।

जीएसटी रद्द करना



GST को समाप्त करने से व्यापारियों पर बोझ कम होगा। घरेलु उत्पादों की कीमतें कम होंगी जिससे हर नागरिक को फायदा होगा। इसकी जगह खाली भूमि पर टैक्स लागू किया जाएगा जिससे भू मालिक अनुपयोगी ज़मीन किराये पर देने लगेंगे। नए व्यापार या आवास के लिए भूमि सस्ते में मिलने लगेगी।

बैलट पेपर से चुनाव कराना



ईवीएम वीवीपेट में लगे काले कांच और light sensor ओं की वजह से अब कागज़ और इलेक्ट्रॉनिक वोट के मिलान से भी चुनाव की निष्पक्षता सिद्ध नहीं होती। इसलिए हमारी मांग है की मतदाताओं को पोलिंग बूथ में बैलट पेपर से वोट करने का विकल्प मिले। ईवीएम रखना या न रखना चुनाव आयोग की मर्ज़ी।

दिल्ली और भारत की सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ उचित समाधान वाला कानून लागू करवाकर हीं किया जा सकता है, इसलिए "आप आगामी चुनावों में" हमारी पार्टी से चुनाव लड़कर, या उचित समाधानों का प्रचार करके अधिक से अधिक नागरिकों को इस विकेंद्रित जनआन्दोलन में जोड़कर, अधिक से अधिक डिमांड खड़ा करने में अपनी भूमिका नीभाएं।

आगे के पन्नों में आपको गरीबी हटाने और अदालतों को सुधारने के लिए प्रस्तावित कानूनों का विवरण मिलेगा

ब्रिटिश साम्राज्य जहां कहा जाता था कि कभी सूर्य अस्त नहीं होता, ग्रीस जहा से सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिम तक के सभी राजाओं को हराया और अभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, इन सब में क्या सबसे बड़ी समानता रही है ??

जवाब - जूरी कोर्ट। मतलब मुकदमों में फैसला देने का अधिकार साधारण नागरिकों के पास होना।

प्रस्तावित जूरी कोर्ट।



इसमें सामान्य प्रक्रिया ये रहती है की जिले की वोटर लिस्ट से 12-15 लोगों की सूची निकाली जाती है और जूरी का गठन होता है। प्रत्येक मुकदमे के लिए अलग जूरी होती है और मुकदमे का फैसला देने के बाद जूरी भंग हो जाती है। जूरी मामला सुनती है और बहुमत सदस्यों का फैसला जूरी का फैसला माना जाता है।

हर मुकदमे के लिए अलग जूरी होने के कारण फैसले 2 हफ्ते के अंदर आ जाते हैं।

जूरी सदस्य अस्थायी होते हैं और 2 हफ्ते के अंदर किसी वकील के लिए उनसे गठजोड़ बनाना बहुत मुश्किल और जोखिमपूर्ण है। इसलिए हमेशा निष्पक्ष फैसले होते हैं।

जूरी न्याय व्यवस्था में विश्वसनीयता बढ़ाती है, क्योंकि हर निर्दोष को विश्वास होता है की नागरिकों की जूरी उसके खिलाफ अन्याय नहीं कर सकती।

भारत में 5 करोड़ केस पेंडिंग है जिसमें लाखों केस 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं। बड़े से बड़ा हाई प्रोफाइल केस भी 10-15 साल में सुलझता है। जूरी सिस्टम के साथ साथ हमें ज़रूरत है की कोर्ट्स की संख्या 20 हज़ार से बढ़ाकर 1 लाख तक करे। हमारा प्रस्ताव है की टैक्स का पैसा नयी अदालतों की संख्या भारत की जनसंख्या के सही अनुपात तक लाने में लगेगा जिससे सारी दिक्कतें जैसे भ्रष्टाचार, महिला असुरक्षा, अंतर जातीय या अंतर धर्म विवाद आदि अपने आप सुधरने लगेंगे।

किसी भी तरह का अनसुलझा मामला हो, हिन्दू-मुस्लिम, अंतर्राष्ट्रीय, महिला-पुरुष, भाई-भाई, व्यापारी-उपभोक्ता, पीड़ित नागरिक-सरकार, राज्य सरकार - केंद्र सरकार, अंत में फैसला तो कोर्ट ही करता है। कोर्ट नहीं सुधरे तो देश में बस ऊपर से थोड़ी बहुत दिखावटी सुधार होंगे, बाकी हर जगह अन्याय ही अन्याय होगा।

अगर आप चाहते हैं की भारत में सही मायने में सत्यमेव जयते हो, तो स्कैन करे, कानून को पढ़ें - समझें और प्रचार करें।



जिस देश में अन्याय है, वो कभी विकसित नहीं हो सकता। चोर, बलात्कारी, दंगाई, आतंकवादी, भ्रष्ट, खूनी - ये सब हमारे बीच आराम से घूमेंगे। अगर आपको लगता है अदालतों में अन्याय नहीं है तो फिर विचार कीजिये की आम आदमी कोर्ट जाने से क्यों डरता है? और क्यों? सोचता है की बहार ही कोई समझौता करलें। इसलिए वोट भी उसी पार्टी को दीजिये जो जूरी कोर्ट का प्रचार करता हो।

हमारा मैनिफेस्टो दुनिया की सबसे क्रन्तिकारी किताब है। इसमें उन 30+ कानूनों का ज़िक्र है जिसमें भारत की सारी परेशानियों का हल है। आप बार कोड स्कैन करे और ये किताब अवश्य पढ़े।

rrpindia.in



tinyurl.com/manifesto00



हमारे साथ मासिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, हर महीने की 5 तारीख को शाम 4:00 बजे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-8 कनॉट प्लेस पोस्ट ऑफिस पर मिलें, हम लोग हर एक महीने 5 तारीख को शाम 5:00 बजे- चुनाव आयोग को, मख्यमंत्री को, और प्रधानमंत्री को, उचित समाधान वाले कानून को लागू करने के लिए चिट्ठी भेजकर नागरिक कर्तव्य दिवस मनाते हैं।

